किया है। यदि कोई राज्य सरकार प्रस्ताव करे, तो हम उनका प्रस्ताव भी मानेंगे और उनकी सहायता भी करेंगे।

श्री सभापतिः अभी तक तो कोई प्रस्ताव आया ही नहीं हैं।

श्री राघुवंश प्रसाद सिंहः महोदय, नेशनल बायो-डीज़ल मिशन जैसे ही शुरू होगा, सब राज्य सरकारों को हम ...(**व्यवधान**)...

श्री राजू परमारः सर, हम चाहते हैं कि कोई स्कीम आपके डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई जाए, डिपार्टमेंट की तरफ से आप स्कीम बनाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राघुवंश प्रसाद सिंहः किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई स्कीम बनती है, तो उसको योजना आयोग से सहमति लेनी पड़ती है। उसकी मंजूरी के बाद ही उसको किया जा सकता है।

देश में सौर ऊर्जा संयंत्र

*204. **श्रीमती सुषमा स्वराजः** क्या गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में सौर ऊर्जा से कितनी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) सौर ऊर्जा संयंत्र अभी तक कहां-कहां स्थापित किए गए हैं;

(ग) सौर ऊर्जा से निर्मित की जाने वाली बिजली अन्य स्रोतों की तुलना में कितनी महंगी या सस्ती होती है; और

(घ) भारत में उपलब्ध सौर ऊर्जा का अभी तक कितना दोहन किया जा चुका है?

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा है

विवरण

(क) सरकार की वित्तीय सहायता से देश में कुल 32 ग्रिड इंटरएक्टिव और प्रकाशवोल्टीय विधुत संयंत्र संस्थापित किए गए है। 2.1 मेवा. की समग्र क्षमता के साथ इन संयंत्रों से एक वर्ष में लगभग 2.5 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) 32 ग्रिड इंटरएक्टिव सौर प्रकाशवोल्टीय विधुत संयंत्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ग) सौर प्रकाशवोल्टीय संयंत्रों से बिजली की यूनिट लागत पारंपरिक स्रोतों और पवन , लघु पनबिजली तथा बायोमास जैसे अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित बिजली की तुलना में बहुत अधिक है। वर्तमान मे, सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों का प्रयोग मुख्यतया, दूरस्थ क्षेत्रों में रोशनी, दूरसंचार और छोटी विधुत जरूरतों जैसे विकेन्द्रित लघु अनुप्रयोगों के लिए किया जा रहा है।

(घ) भारत को प्रतिवर्ष 5,000 ट्रिलियन किवा घंटा से अधिक के बराबर सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, जो देश की कुल ऊर्जा जरूरत से बहुत अधिक है। तथापि, सौर ऊर्जा प्रणालियों की उच्च आरंभिक लागत के कारण अब तक देश में समग्र रूप से लगभग 82 मेवा० क्षमता की लगभग 12.8 लाख सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त सौर जल तापन अनुप्रयोगों के लिए लगभग 11 लाख वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र संस्थापित किया गया है, जो लगभग 770 मवा० क्षमता के बराबर है।

विवरण-I

ग्रिड-इंटरएक्टिव सौर प्रकाशवोल्टीय संयंत्रों की सूची

क्रम सं०	परियोजना का नाम	नोडल एजेंसी	राज्य	क्षमता (किवा० पीक)
1	2	3	4	5
1.	एपीएसईबी भवन, हैदराबाद	एपीटीआरएएन सीओ	आंध्र प्रदेश	100
2.	नेल द्वीप समूह	बिजली विभाग	अंडमान एंव निकोबार	50
3.	हैवलोक द्वीप समूह	बिजली विभाग	अंडमान एंव निकोबार	50
4.	अपेडा भवन	अपेडा	अरूणाचल प्रदेश	25
5.	विद्युती भवनम	एएनईआरटी	केरल	25
6.	किल्टन द्वीप समूह	बिजली विभाग	लक्षद्वीप	100
7.	मिनिकॉय	बिजली विभाग	लक्षद्वीप	100
8.	कडमट	बिजली विभाग	लक्षद्वीप	150
9.	एंड्रोट द्वीप समूह	बिजली विभाग	लक्षद्वीप	100
10.	कवारती	बिजली विभाग	लक्षद्वीप	100

1	2	3	4	5
11.	अगाती	बिजली विभाग	लक्षद्वीप	100
12.	कल्पेनी द्वीप समूह	बिजली विभाग	लक्षद्वीप	100
13.	जैतपुरा कलां	एमपीयूवीएन	मध्य प्रदेश	100
14.	मुख्य सचिवालय भवन	डीआरडीए	पांडिचेरी	25
15.	बाजक	पेडा	पंजाब	50
16.	खाटकर कलां	पेडा	पंजाब	200
17.	पेडा भवन, चंडीगढ़	पेडा	पंजाब	25
18.	मिनी सचिवालय,चंडीगढ़	पेडा	पंजाब	50
19.	विधान भवन,जयपुर	रेडा	राजस्थान	25
20.	गांव गोरिर	आरआरईसीएल	राजस्थान	100
21.	सरकारी सचिवालय,जयपुर	रेडा	राजस्थान	25
22.	एसजी पलायम	टीएनईबी	तमिलनाडु	25
23.	एसजी पलायम	टीएनईबी	तमिलनाडु	25
24.	कल्याणपुर-अलीगढ़	नेडा	उत्तर प्रदेश	100
25.	हरिया	नेडा	उत्तर प्रदेश	100
26.	सराय सादी	नेडा	उत्तर प्रदेश	100
27.	नेडा भवन,लखनऊ	नेडा	उत्तर प्रदेश	25
28.	आईआरईपी प्रशिक्षण केन्द्र, चिनहट	नेडा	उत्तर प्रदेश	25
29.	विधान भवन,देहरादून	ऊरेडा	उत्तरांचल	25
30.	सचिवालय, देहरादून	ऊरेडा	उत्तरांचल	25
31.	विद्युत भवन कोलकाता	वब्रेडा	पश्चिम बंगाल	25
32.	विकल्प शक्ति भवन कोलकाता	वब्रेडा	पश्चिम बंगाल	25
	कुल			2100

Solar energy plants in the country

†*204. SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Will the Minister of NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) the quantum of electricity being generated from solar energy in India;

(b) the places where solar energy plants have been set up, so far;

(c) to what extent the electricity generated from solar energy is cheaper or dearer compared to that from other sources; and

(d) the quantum of available solar energy in India, tapped so far?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI VILAS MUTTEMWAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) A total of 32 grid interactive solar photovoltaic power plants have been installed in the country with financial support from the Government. These plants, with aggregate capacity of 2.1 Megawatt, are estimated to generate about 2.5 million units of electricity in a year.

(b) The list of 32 grid interactive solar photovoltaic power plants is given at enclosed Statement-I (See below).

(c) The unit cost of electricity from solar photovoltaic plants is very high compared to electricity generated from conventional sources and other renewable energy sources such as wind, small hydro and biomass. At present, solar photovoltaic systems are mainly being used for decentralized niche applications such as lighting, telecommunication and small power requirements in remote areas.

(d) India receives solar energy equivalent to over 5,000 trillion kWh per year, which is far more than the total energy requirement of the country. However, due to high initial cost of solar energy systems, so far around 12.8 lakh solar photovoltaic systems aggregating to about 82 Megawatt capacity have been installed in the country. In addition about 11 lakh square metre collector area has been installed for solar water heating applications, which is equivalent to about 770 Megawatt capacity.

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

Statement-I

List of Grid Interactive Solar Photovoltaic Plants

SI. No.	Name of Project	Nodal Agency	State	Capacity (kWp)
1	2	3	4	5
1.	APSEB Building, Hyderabad	APTRANCO	Andhra Pradesh	100
2.	Neil Island	Elec. Dept.	Andaman & Nicobar	50
3.	Havelock Island	Elec. Dept.	Andaman & Nicobar	50
4.	APEDA Building	APEDA	Arunachal Pradesh	25
5.	Viduthi Bhawanam	ANERT	Kerala	25
6.	Kiltan Island	Elec. Dept.	Lakshadweep	100
7.	Minicoy	Elec. Dept.	Lakshadweep	100
8.	Kadamat	Elec. Dept.	Lakshadweep	150
9.	Andrott Island	Elec. Dept.	Lakshadweep	100
10.	Kavaratti	Elec. Dept.	Lakshadweep	100
11.	Agatti	Elec. Dept.	Lakshadweep	100
12.	Kalpeni Island	Elec. Dept.	Lakshadweep	100
13.	Jaitpura Kalan	MPUVN	M.P.	100
14.	Chief Secretariat Building	DRDA	Pondicherry	25
15.	Bajak	PEDA	Punjab	50
16.	Khatkar Kalan	PEDA	Punjab	200
17.	PEDA Building, Chandigarsh	PEDA	Punjab	25
18.	Mini Secretariat, Chandigarh	PEDA	Punjab	50
19.	Vidhan Bhawan, Jaipur	REDA	Rajasthan	25
20.	Viage Gorir	RRECL	Rajasthan	100
21.	Govt. Secretariat, Jaipur	REDA	Rajasthan	25
22.	SG Pallayam	TNEB	Tamil Nadu	25
23.	SN Pallayam	TNEB	Tamil Nadu	25

1	2	3	4	5
24.	Kalyanpur-Aligarh	NEDA	Uttar Pradesh	100
25.	Harriya	NEDA	Uttar Pradesh	100
26.	Sarai Sadi	NEDA	Uttar Pradesh	100
27.	NEDA Building, Lucknow	NEDA	Uttar Pradesh	25
28.	IREP Trg. Centre, Chinhat	NEDA	Uttar Pradesh	25
29.	Vidhan Bhawan, Dehradun	UREDA	Uttaranchal	25
30.	Secretariat, Dehradun	UREDA	Uttaranchal	25
31.	Bidyut Bhawan, Kolkata	WBREDA	West Bengal	25
32.	Bikalp Shakti Bhawan, Kolkata	WBREDA	West Bengal	25
	TOTAL:			2100

श्रीमती सुषमा स्वराजः सभापति जी, मैंने प्रश्न के भाग "घ"में यह जानना चाहा था कि देश में कितनी सौर ऊर्जा उपलब्ध है और उसमें से कितनी क्षमता का दोहन किया जा चुका है? बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी मंत्री जी के उत्तर में मिली है। उन्होंने सदन का बताया है कि देश में 5000 ट्रिलियन किलोवाट सौर ऊर्जा उपलब्ध है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि यह देश की सारी ऊर्जा की जरूरत से ज्यादा है। सभापति जी, बिलियन नहीं, 5000 ट्रिलियन किलोवाट,जो देश की सारी ऊर्जा जरूरत से ज्यादा है, इतनी सौर ऊर्जा देश में उपलब्ध है। लेकिन इसके बाद उन्होंने दोहन के संबंध में जानकारी दी कि मुल 82 मेगावॉट क्षमता अभी तक हमने प्रकाशवोल्टीय प्रणाली से दोहन की है और लगभग 770 मेगावाट हमने सोलर वॉटर हीटर्स के लिए दोहन किए हैं, यानी अगर हम दोनों आंकड़ों को जोड़ ले, तो भी कुल 850 मेगावाट के करीब की क्षमता का हमने दोहन किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि देश में बिजली का इतना गंभीर संकट है कि हम लोग न्यूक्लीयर पावर के नाम पर अमेरिका जैसे देश में अहितकारी समझौते तक कर रहे हैं, तो क्यो नहीं हम इस सौर ऊर्जा का दोहन करके अपने देश के जरूरत को पूरा कर सकते हैं?

श्री विलास मुत्तेमवारः माननीय सभापति जी, माननीय सदस्या से जो प्रश्न पूछा है, उसका मैं स्वागत करता हूं। यह बात सही है कि देश में 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा से अधिक के बराबर

सौर ऊर्जा उपलब्ध है, लेकिन मेरे उत्तर के "ग" भाग में मैंने कहा है कि अक्षय ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं, उससे सौर ऊर्जा की लागत बहुत ज्यादा आती है और उससे इसे दोहन करने में कठिनाइयां आती है। इसलिए यह तय किया जाए कि इस ऊर्जा का दोहन करना चाहिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दूसरे स्रोतों में जो लागत आती है, उससे ज्यादा सौर ऊर्जा से 12 रुपए से 20 रुपए प्रति किलावॉट घंटा की लागत इसमें आती है और मैं समझता हूं कि वह बहुत ज्यादा होने से इसमें कठिनाइयां आती हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराजः सभापति जी, मंत्री जी ने 'ग' में यह कहा है, लेकिन 'घ' मे यह कहा है कि आरम्भिक लागत है। आपने अपने उत्तर में 82 मेगावाट कहा है, इसीलिए मैंने उसका अंग्रेजी भाग भी देखा है, तो उसमें भी हाई इनिशियल कॉस्ट लिखा हैं सभापति जी, मैं माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि सौर ऊर्जा से संयंत्र में आरंभिक लागत जरूर ज्यादा लगती है, लेकिन उसके बाद तो वह मुफ्त जैसी बिजली हो जाती है। क्योंकि उसके लिए आपको किसी इंधन की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए न कोयला चाहिए, न गैस चाहिए और न ही न्यूक्लियर फ्यूअल चाहिए। यह तो भगवान सूर्य चमक रहे हैं और जिस प्रखरता से चमक रहे हैं, वह सौर ऊर्जा आपको मिल रही है। मैं यह कहना चाहती हूं कि आरंभिक लागत होने के बावजूद अगर बाद में मुफ्त जैसी बिजली देते हैं, तो आरंभिक लागत तो आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। क्या आपने कभी समग्रता का आकलन किया है? आरंभिक लागत ज्यादा होने के बावजूद जो कुल बिजली कुछ वर्षो तक मुफ्त के तौर पर दी जाएगी, उससे आरंभिक लागत निकल आएगी तो क्यों नहीं हम सौर ऊर्जा का दोहन करते और अपने देश की जरूरत का पूरा करते हैं?

श्री विलास मुत्तेमवारः महोदय, माननीय सदस्या जो कह रही हैं, मैं उससे सहमत हूं जहां पर बिजली की कमी है, वहां पर राज्य सरकारों को इसके लिए इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। जो इस प्रकार के स्रोत हैं, हमारे मंत्रालय का उत्तरदायित्व उनका परिचालन करना और उनका रिसर्च एंड डेवलमेंट करना है। जैसा मैंने कहा है कि सोलर फोटो वोल्टिक के रिसर्च एंड डेवलमेंट में सौर सेल की जो क्षमता है, वह 15 से 17 परसेंट बढ़ाना है। इस तरह के कार्य को हमारा मंत्रालय देखता है। जैसे कि यह पांच हजार ट्रिलियन सौर ऊर्जा है, यह प्राप्त हो सकती है, तो यह इनिशिएटिव पर है। जहां पर राज्य सरकारें बिजली की किल्लत को देखती हैं, हम वहां पर जनरेट नहीं करते हैं। हमारा मंत्रालय जनरेट नहीं करता है, वह जनरेशन करना तो राज्य सरकारों पर निर्भर है। मैं समझता हूं कि इसका उपयोग किया जा सकता है।

श्रीमती सुषमा स्वराजः महोदय, राम जेठमलानी जी जैसा सवाल तो इन पर भी लागू होता है कि कुछ सेंसिबल डिपार्टमेंट भी करेगा या नहीं, केवल राज्य सरकारों को जिम्मेदारी देकर आप बरी नहीं हो सकते हैं।

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, it is quite dear that the country is facing a major energy crisis, and dearly, the most non-polluting and the most desirable energy that we can get is from the sun. I am slightly disappointed with the Minister's reply that the initiative for this must come from the States. Sir, this is a new technology. Around the world, technological breakthroughs are taking place. May I ask of the Minister whether in view of the fact, as has been pointed out that solar energy, in fact, is the only energy that is going to save the humanity in the 21st century, the Ministry itself will take some major steps? We have some of the best scientists in the world; we have great technologists. We should be able to make the breakthroughs. You cannot expect the State Governments to make a breakthrough in this. It is your responsibility, Mr. Minister, to take a positive, dynamic initiative to try and bring down the cost of solar energy so that we can get an alternative non-polluting source of energy.

श्री विलास मुत्तेमवारः सभापति जी, मैं बार-बार यह कह रहा हूं कि यह सोर्स एवेलेबल है। जहां तक हमारे मंत्रालय का सवाल है कि इसको उपयोग में लाने के लिए, आज जो यह बिजली महंगी है, उसको कम करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है। जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा है कि दुनिया में अक्षय ऊर्जा प्रयोग हो रहे हैं, तो हम भी इसमें पीछे नहीं है। हमारे यहां भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। इसके लिए कोई राज्य सरकारों ने इनिशिएटिव भी लिया है। अगर इसकी कॉस्ट में 20 प्रतिशत की कमी आती है और लोग उसका ज्यादा उपयोग करते हैं तो यह स्त्रोत सफल हो सका है। जहां तक मंत्रालय को इनिशिएटिव लेने का सवाल है तो मैं बार-बार यह कहरहा हूं कि आज हम जनरेशन नहीं कह रहे हैं और इसीलिए इसको करने में हमारी कठिनाई है।

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: Sir, I was surprised to hear the reply of the hon. Minister, I remember when Shri Shivraj V. Patil was the Minister for Science and Technology and this alternate source of energy was under that Ministry, he told that research was being going on in this field. He travelled to the United States and visited a lot of projects there. It is not only photo voltaic cells, but also there are other ways of getting solar energy converted into electricity. Now, I would like to know from the hon. Minister whether there is any proposal to do research to find out other ways, other than photo voltaic cells, of getting solar energy converted into electricity because the Minister said that photo voltaic cells are expensive. Sir, in the Government houses in Delhi, we have got solar heaters for heating water. Is there any proposal before the Government

that would extend it to heating in houses also because a lot of electricity will be saved? We are in Delhi, we are under the Central Government, and we do not have to get a proposal from the State Government. Is there any proposal before you?

श्री विलास मुत्तेमवारः सौर ताप बिजली से पानी गर्म करने की योजना, जैसाकि आपने कहा, हमारे यहां दिल्ली में संसद सदस्यों को भी उपलब्ध कराएगी, ताप करने का आपका जो प्रश्न है, उस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के सामने नहीं है, लेकिन इस पर विचार किया जाएगा।

PROF. RJ. KURIAN: Sir, the solar energy is the energy of the future.

डा० (श्रीमती) नजमा हेपतुल्लाः सभापति जी, उन्होंने पहले का जवाब तो दिया नहीं, जबकि वह मेजर क्वेश्चन हैं।

श्री मूल चन्द मीणाः हो गया, पूरा जवाब हो गया।

डा० (श्रीमती) नजमा हेपतुल्लाः कैसे हो गया? आप लोग हो गया, हो गया कैसे कह देते हैं।

PROF. P.J. KURIAN: The fossil fuel is being depleted and the solar energy is the energy of the future. Hon. Minister said that the cost of solar energy production is very high because of the cost of photo-voltaic cells. I have two points. Firstly, what is important is to conduct research in order to reduce the cost of photo-voltaic cells. I would like to know whether the Government is thinking in that direction. You are leaving it to the State Governments and I would say that the Central Government should take initiative in that direction and spend more money and utilise the service of our scientists. If necessary, get the technology from outside, if it is available outside, so that the cost of production of solar energy is reduced.

Secondly, a lot of energy is used today for heating water in the houses. Why not a legislation be framed saying that all Government houses or new houses would use only the solar energy for water heating purpose? That is possible. Why not? There can be a legislation to say that all new houses will use solar energy for water heating purpose. That is possible. Why do not you think of a legislation?

श्री विलास मुत्तेमवारः सभापति जी, मैंने सारी चीजें राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ी हैं। मैंने अपनेजवाब में बताया कि रिसर्च एण्ड डेवलेपमेंट के द्वारा सौर सेल की क्षमता को 15 से 17 परसेंट तक करना, सिलिकन वेपर की मोटाई कम करना, नई विधि की थिन फिल्म सेल बनाना, इत्यादि कुछ

प्रमुख लक्ष्य हैं। इन प्रयासों से कीमत में 20 प्रतिशत की कमी आ सकती है। दूसरा, माननीय सदस्य ने सोलर वाटर हीटर के बारे में बताया, मैं उनके लिए बताया चाहता हूं कि मंत्रालय ने अभी एक कार्यक्रम घोषित किया है, जिसके लिए व्यापक प्रतिसाद मिल रहा है। कुछ काज्य सरकारें और वहां की महापालिकाओं ने इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने यह कम्पलसरी कर दिया है, जिसमें वे हाउस टैक्स में रियायत देते हैं। हमारे मंत्रालय की तरफ भी इस चीज को बढ़ावा देने के लिए पहले से पांच परसेंट इंट्रस्ट पर लोन दिलाया जाता था, अब इसे दो परसेंट इंट्रस्ट पर कर दिया है और इसे व्यापक प्रतिसाद मिल रहा है।

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, there are many schemes to generate power from the solid waste together with the industrial waste in different parts of the country. There is also a definite proposal for generating power from tidal waves in the Sundarbans area of West Bengal. How are such schemes progressing in the country?

श्री विलास मुत्तेमवारः सभापति जी, इनका प्रश्न सोलर से संबंधित नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने सुंदरबन में एक प्रस्ताव की बात कही है, जिसमें लहरों सें बिजली उत्पादन की बात है। ऐसा एक प्रस्ताव पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से आया है, जिसके लिए, डी०पी०आर० के लिए हमारे मंत्रालय ने पैसा दिया है। बीच में एन्वायरमेंट एण्ड फोरेस्ट मिनिस्ट्री की क्लियरेंस की वजह से वह प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया था, लेकिन वह प्रस्ताव अभी हमारे पास आना है। हमारे हिन्दुस्तान में पहली बार उस पर प्रयोग होने जा रहा है, जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम उसमें मदद करने वाले हैं।

SHRI PRASANTACHATTERJEE: Together with solid waste and industrial waste ...*(Interruptions)*...

श्री विलास मुत्तेमवारः हम करेंगे।

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Sir, Jammu & Kashmir State is extremely deficient in electricity. Last year, the Prime Minister made contribution for promotion and generation of hydro electrice power. But those units will take time. Would the hons. Minister consider setting up two units for generation of solar energy, one in Jammu, and one in Srinagar? ...*(Interruptions)*... One in Ladakh. ...*(Interruptions)*... Why not? ...*(Interruptions)*... During winter, they do not have electricity. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You have put your question. Let him reply. ...*(Interruptions)*...

श्री विलास मुत्तेमवारः सभापति जी, जम्मू और कश्मीर में solar photovoltaic से घरों को बिजली देने का कार्यक्रम अभी चल रहा है। जो इन्होंने संयंत्र लगाने की बात कही है, राज्य सरकार की तरफ से अगर हमारे पास ऐसा प्रस्ताव आता है तो जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां ...(**व्यवधान**)...

प्रो० सैफुद्दीन सोजः आप प्रस्ताव का क्यों इंतेजार करेंगे ...(**व्यवधान**)...

پروفیسر سیف الدین سوز: آپ پرستاؤ کا کیوں انتظار کریں گے؟ .....مداخلت.....

MR. CHAIRMAN: Do not disturb him. ...*(Interruptions)*...

श्री विलास मुत्तेमवारः उन्हीं को करना पड़ता है ...(**व्यवधान**)...

प्रो० सैफुद्दीन सोजः नोडल एजेंसी तो स्टेट गवर्नमेंट है ...(**व्यवधान**)...

پروفیسر سیف الدین سوز: نادل ایجنسی تو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے۔ .....مداخلت.....

MR. CHAIRMAN: Prof. Soz, please do not disturb him.
PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Kindly show the gesture. ...*(Interruptions)*...

श्री विलास मुत्तेमवारः मैंने बताया है कि अगर आ जाता है तो हम उस पर ...(**व्यवधान**)...

प्रो० सैफुद्दीन सोजः आप कहिए कि आप तैयार हैं।

پروفیسر سیف الدین سوز: آپ کہئے کہ آپ تیار ہیں۔

श्री विलास मुत्तेमवारः हां, हम तैयार हैं।

ग्रामीण पेय-जल योजना हेतु आवंटन

*205. **श्री कलराज मिश्रः** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत निधियों आवंटित करते समय अपनाये जाने वाले मानकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों द्वारा उक्त निधियों का ठीक तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

†Transliteralion in Urdu script.